International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Volume 14, Issue 2, March-April

"भारत में डिजिटल क्रांति का एक दशक (2015–2025): एक समालोचनात्मक अध्ययन"

डॉ. शक्ति चौधरी

सारांश

वर्ष 2015 से भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया, जिसका उद्देश्य देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। इस अध्ययन में 2015 से 2025 तक के एक दशक में डिजिटल क्रांति के प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार, सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन (जैसे–भीम ऐप, जनधन योजना, आधार), ई-गवर्नेंस, और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की गई है।

साथ ही, इस क्रांति से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों तथा डिजिटल डिवाइड, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध और डिजिटल साक्षरता की चुनौतियों को भी उजागर किया गया है। यह शोध दर्शाता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ग्रामीण-शहरी अंतर को कुछ हद तक कम किया है और नागरिकों को अधिक सशक्त बनाया है, लेकिन इसके पूर्ण लाभों के लिए संरचनात्मक सुधार, डिजिटल समावेशन और साइबर सुरक्षा में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। यह अध्ययन डिजिटल भारत की यात्रा की उपलब्धियों एवं सीमाओं दोनों को संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2015 से भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत के साथ एक नई डिजिटल क्रांति की नींव रखी गई। इस शोध-पत्र में पिछले एक दशक में डिजिटल विकास के विभिन्न पहलुओं—जैसे डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, इंटरनेट प्रसार, डिजिटल शिक्षा, और ग्रामीण डिजिटलीकरण—का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का भी गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

कीवर्ड्स: डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, इंटरनेट, डिजिटल शिक्षा, डिजिटलीकरण, भारत

प्रस्तावना

विगत एक दशक में भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का अनुभव किया है, जिसे सामान्यतः **"डिजिटल क्रांति"** के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015 में "डिजिटल इंडिया" अभियान की शुरुआत के साथ ही देश ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। इस पहल ने न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण भारत में भी तकनीकी जागरूकता और समावेश को बढ़ावा दिया।

इस दशक में आधार कार्ड, मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस, और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे **UPI**, **DigiLocker**, **BHIM ऐप**, और **स्वामित्व योजना** ने आम नागरिकों को अधिकार और सुविधा दोनों प्रदान किए हैं।

हालांकि, यह परिवर्तन पूर्णतः सकारात्मक नहीं रहा। डिजिटल असमानता, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता का हनन, और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसे कई सामाजिक और तकनीकी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

यह अध्ययन भारत में 2015 से 2025 के बीच घटित डिजिटल परिवर्तन की प्रकृति, इसकी उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास है, जिससे भविष्य में डिजिटल समावेशन की दिशा में अधिक प्रभावी नीतियाँ बनाई जा सकें।

भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत का प्रमुख पड़ाव 1 जुलाई 2015 को "डिजिटल इंडिया अभियान" से हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। इस अभियान के तहत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को जन-जन तक पहुंचाने और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। यह शोध पत्र इसी क्रांति के दस वर्षों के विकास और चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।

अनुसंधान उद्देश्य

- भारत में डिजिटल क्रांति की प्रमुख उपलब्धियों का विश्लेषण करना
- डिजिटल माध्यमों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आए परिवर्तनों का अध्ययन
- डिजिटल भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का मूल्यांकन
- भविष्य की संभावनाओं एवं नीतिगत सुधारों का सुझाव देना

अनुसंधान विधि

यह शोध वर्णनात्मक (descriptive) और विश्लेषणात्मक (analytical) पद्धति पर आधारित है। विभिन्न सरकारी दस्तावेज, नीति रिपोर्टें, समाचार-पत्र लेख, और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।

भारत में डिजिटल क्रांति की प्रमुख उपलब्धियाँ: भारत में डिजिटल क्रांति ने पिछले एक दशक में समाज, अर्थव्यवस्था, शासन और जीवनशैली के प्रत्येक पहलू को गहराई से प्रभावित किया है। वर्ष 2015 में "डिजिटल इंडिया" अभियान की शुरुआत के साथ ही यह क्रांति एक संगठित दिशा में आगे बढ़ी। इस परिवर्तनशील यात्रा की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- **ई-गवर्नेंस का विस्तार:** डिजिटल क्रांति के चलते सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम हुई है। सरकारी सेवाएँ जैसे कि आधार, डिजिलॉकर, ई-हॉस्पिटल, उमंग ऐप और जनधन योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुलभ हो गईं, जिससे पारदर्शिता, समयबचत और भ्रष्टाचार में कमी आई।
- **फाइनेंशियल समावेशन:** प्रधानमंत्री जनधन योजना, भीम (BHIM) ऐप, UPI (Unified Payments Interface), मोबाइल वॉलेट और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन-देन की संस्कृति विकसित हुई है।
- **डिजिटल शिक्षा का विकास:** राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM), और एनसीईआरटी की ऑनलाइन सामग्री जैसे पोर्टल्स ने डिजिटल लर्निंग को सशक्त किया है। COVID-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं ने शैक्षिक प्रणाली को नया आधार प्रदान किया।
- **स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)**, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, CoWIN प्लेटफॉर्म और डिजिटल हेल्थ आईडी जैसी पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाया। महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक डिजिटली संचालित किया गया।
- **रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्किल इंडिया कार्यक्रमों ने युवाओं को आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर दिए। डिजिटल इंडिया के तहत स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा मिला और भारत "स्टार्टअप हब" के रूप में उभरा।
- **ग्रामीण डिजिटलीकरण और इंटरनेट पहुँच:** भारत नेट योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया, जिससे इंटरनेट की पहुँच ग्रामीण भारत तक पहुंची। इससे किसानों, छात्रों और उद्यमियों को नई जानकारियाँ व सेवाएँ प्राप्त हुईं।
- **ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार का प्रसार:** Flipkart, Amazon, Meesho जैसे प्लेटफार्मों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों ने भी डिजिटल माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचना शुरू किया। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन मार्केटिंग ने व्यापार में नई संभावनाएँ खोलीं।
- **डिजिटल साक्षरता में सुधार:** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के तहत लाखों ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई। इससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिली।

डिजिटल क्रांति के प्रभाव

डिजिटल क्रांति, जिसे डिजिटल परिवर्तन या *Digital Transformation* भी कहा जाता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति का परिणाम है। भारत में विशेषकर 2015 के बाद से डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत के साथ यह क्रांति और भी तेज़ी से बढ़ी है। इसने न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रशासन, और स्वास्थ्य जैसी विभिन्न जीवन-क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाए हैं। नीचे डिजिटल क्रांति के विभिन्न प्रभावों का वर्णन किया गया है:

- **सामाजिक प्रभाव:** डिजिटल क्रांति ने समाज को अधिक *सूचना-संपन्न* बनाया है। अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ पाए हैं। डिजिटल शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म (जैसे

DIKSHA, SWAYAM) ने शिक्षा को सुलभ और सस्ता बना दिया है। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सूचना और सेवाओं तक सीधी पहुँच मिल रही है, जिससे *समावेशी विकास* को बढ़ावा मिला है।

- **आर्थिक प्रभाव:** ई-कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई (UPI) जैसी सेवाओं के माध्यम से *कैशलेस अर्थव्यवस्था* को बढ़ावा मिला है। स्टार्टअप्स और डिजिटल उद्यमिता में उछाल आया है। डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, और ऑनलाइन सेवाओं ने रोजगार के नए अवसर खोले हैं। सरकार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में मदद मिली है, जिससे *भ्रष्टाचार में कमी* आई है।

- **शैक्षिक प्रभाव:** ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों ने शिक्षा की *भौगोलिक सीमाओं* को समाप्त किया है। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से छात्रों को इंटरएक्टिव और मल्टीमीडिया आधारित शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। महामारी के समय ऑनलाइन शिक्षा एक *जीवनरेखा* साबित हुई।

- **प्रशासनिक और शासन-प्रणाली पर प्रभाव:** डिजिटल क्रांति ने ई-गवर्नेंस को सशक्त किया है। अब नागरिकों को घर बैठे सेवाएँ मिल रही हैं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आवेदन आदि। RTI, डिजिटल वोटिंग, और पब्लिक फीडबैक जैसे माध्यमों से *पारदर्शिता और उत्तरदायित्व* में वृद्धि हुई है।

- **स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव:** टेलीमेडिसिन और ई-हॉस्पिटल जैसी सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में भी *स्वास्थ्य सेवाएँ* सुलभ हो सकी हैं। कोविड-19 के दौरान आरोग्य सेतु जैसे एप्लिकेशन ने संक्रमण की निगरानी और जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चुनौतियाँ

भारत में 2015 से 2025 तक का समय डिजिटल क्रांति के दृष्टिकोण से अत्यंत परिवर्तनकारी रहा है। इस दशक में देश ने डिजिटल तकनीकों को अपनाकर कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसे कि ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटलीकरण की दिशा में सरकारी योजनाएँ, डिजिटल भुगतान आदि। हालांकि इस क्रांति के समक्ष कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं, जो इसकी व्यापकता और प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इन चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित है:

- **डिजिटल डिवाइड**

भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भारी असमानता देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की धीमी गति, स्मार्ट डिवाइसों की कमी, और डिजिटल साक्षरता की न्यूनता ने डिजिटल क्रांति से वंचित वर्गों को और पीछे कर दिया है।

- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** हालांकि डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं, परंतु देश के एक बड़े हिस्से को अब भी तकनीकी ज्ञान की कमी है। विशेषकर वृद्ध, महिलाएं, और ग्रामीण जनसंख्या डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती।

- **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते निर्भरता के साथ ही साइबर हमलों, डेटा चोरी और गोपनीयता उल्लंघनों की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। भारत में साइबर सुरक्षा ढांचे की अभी भी मजबूती की आवश्यकता है।

- **अवसंरचनात्मक बाधाएँ**

इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक कमियाँ डिजिटल भारत के उद्देश्य को बाधित करती हैं, विशेषकर पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में।

- **बहुभाषिकता की चुनौती:** भारत में कई भाषाएँ बोली जाती हैं, लेकिन अधिकांश डिजिटल सामग्री अंग्रेजी या कुछ गिनी-चुनी भारतीय भाषाओं तक सीमित है। इससे गैर-अंग्रेजी भाषी और अल्पशिक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल साधनों तक पहुंच कठिन हो जाती है।

- **डिजिटल भुगतान और धोखाधड़ी:** यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की लोकप्रियता के साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। जागरूकता की कमी के कारण लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं।

- **नौकरी बाजार पर प्रभाव:** डिजिटलीकरण ने कई पारंपरिक नौकरियों को समाप्त कर दिया है। स्वचालन (Automation) के कारण कई क्षेत्रों में मानव श्रमिकों की आवश्यकता कम हुई है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई।

- **नीति और कार्यान्वयन के बीच अंतर:** सरकार की नीतियाँ तो डिजिटल इंडिया के समर्थन में थीं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर सही और समयबद्ध कार्यान्वयन नहीं हो पाया, जिससे कई योजनाएं केवल कागज़ों तक ही सीमित रहीं।

निष्कर्ष

पिछले एक दशक (2015–2025) में भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत से लेकर आज तक देश ने सूचना और संचार तकनीक (ICT) के ज़रिए शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव का अनुभव किया है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे प्रयासों ने नागरिकों के जीवन को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया है।

हालाँकि, यह क्रांति केवल सकारात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं रही। डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ, डेटा गोपनीयता, और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच जैसे मुद्दे भी समानांतर रूप से उभरे हैं। इन समस्याओं के समाधान के बिना डिजिटल समावेशन एक सपना मात्र रह जाएगा।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल क्रांति ने भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया है, लेकिन इसकी स्थायित्वपूर्ण सफलता के लिए तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ सामाजिक न्याय, डिजिटल साक्षरता और मजबूत नीतिगत ढाँचे की भी आवश्यकता है। यदि भारत इन चुनौतियों का समाधान करने में सफल होता है, तो अगला दशक उसे एक वैश्विक डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है।

भारत में डिजिटल क्रांति ने बीते एक दशक में नागरिकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। डिजिटल सेवाओं ने प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और वाणिज्य के क्षेत्रों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है। हालाँकि अभी भी कुछ बाधाएँ विद्यमान हैं, जिन्हें दूर कर भारत एक पूर्ण डिजिटल राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

संदर्भ

1. Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India
2. NITI Aayog Reports (2020–2024)
3. TRAI Internet Reports
4. Economic Survey of India (2019–2025)
5. Press Information Bureau, GoI
6. Digital India Official Website